प्याज के दाम घटे, फसल पशुओं से चरवाई

नीमच,22 नवम्बर . जिले में प्याज के दाम लुढ़के तो किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया. प्याज के दाम गिरने से किसानों में नाराजगी का माहौल है.

जिले के एक किसान ने खेत में खड़ी प्याज की फसल को रोटावेटर से हंकवा दिया जबकि दूसरे किसान ने पशु की फसल में पशु चरा दिए. किसानों का कहना है कि प्याज की फसल के दाम बेहद कम है, इसके कारण फसल का लागत मूल्य निकालना भी मुश्किल हो रहा है. कृषि उपज मंडी नीमच प्रदेश के बड़ी मंडियों में शामिल होकर ए ग्रेड की मंडी है. मंडी की लहसुन और प्याज के मामले में देश व प्रदेश में एक अलग ही पहचान है. साथ ही जिले में लहसुन और प्याज की पैदावार भी अधिक होती है. मंडी में इन दिनों प्याज की औसत आवक हो रही है लेकिन इसके बावजूद मंडी में प्याज 2 से 15 रुपये किलो के भाव से बिक रहा है. क्विंटल में आकलन करें तो मंडी में प्याज 200 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल से मान से बिक रहा है.

लागत तक न निकलने से नाराजगी बढ़ी

बाजार में प्याज के दाम नहीं मिल रहे

सब्जी मंडी में खेरची में भी प्याज के दाम 10 से 20 रुपये किलो बने हुए हैं. प्याज के दामों में गिरावट से जिले के किसानों के सामने प्याज की फसल का लागत मूल्य निकालना भी मुश्किल हो रहा है और किसान इसे लेकर अनूठे तरीके से विरोध भी दर्ज करा रहे हैं .दो दिन पूर्व जिले की जीरन तहसील के ग्राम कराडि?ा महाराज के कृष्णपाल सिंह राणावत ने अपने खेत में खड़ी प्याज की फसल को रोटावेटर से हंकवा दिया और खेत को नई फसल के लिए तैयार कर लिया. वहीं नीमच तहसील के ग्राम रावतखेड़ा के विशाल सिंह पुत्र रतन सिंह ने खेत में प्याज की फसल में पशु चरा लिए और प्याज की फसल का उपयोग पशुओं का पेट भरने में किया. दोनों ही किसानों ने यह कदम प्याज के दाम बेहद कम मिलने पर उठाया. इसी तरह जिले के अन्य क्षेत्रों में प्याज के दाम कम मिलने से किसानों में नाराजगी का माहौल है. किसान प्याज के दाम पर खून के आंसू बहा रहे हैं. जयसिंहपुरा के किसान प्रेमप्रकाश पाटीदार ने बताया कि मंडी और बाजार में प्याज के दाम नहीं मिल रहे हैं. किसानो के सामने प्याज के फसल का लागत मूल्य निकालना मुश्किल हो रहा है, ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएगा. वर्षा की अधिकता और बेमौसम वर्षा के साथ बीमारियों ने सोयाबीन की फसल को बर्बाद कर दिया था. अब प्याज की फसल के दाम सही नहीं मिल रहे हैं. किसान बेहद मुसीबत में हैं.

पूर्व पटवारी सहित 7 पर एफआईआर

- मऊगंज में मामला कंप्यूटरीकृत खसरे का

रीवा, 22 नवम्बर, मऊगंज जिले के हनुमना तहसील क्षेत्र में खसरा प्रविष्टियों में अवैध परिवर्तन के गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है.

अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा भेजे गए आधिकारिक पत्र के आधार पर हनुमना थाना पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. मामले का खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने शुक्रवार को मीडिया के सामने किया है. एडिसिनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि सूचना देने वाले नायब तहसीलदार बुद्धसेन मांझी ने थाना हनुमना पहुंचकर स्थ्रू कार्यालय द्वारा जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की. पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम कोलहा, पटवारी हल्का धौसड़, राजस्व निरीक्षक मंडल पहाड़ी की आराजी नंबर 353, रकवा 0.170 हेक्टेयर में वर्ष 2007-08 से 2009-10 के बीच कंप्यूटरीकृत खसरे में अनाधिकृत रूप से प्रविष्टियों में परिवर्तन किए गए. यह मामला हाईकोर्ट के आदेश के बाद संज्ञान में आया था, जिसमें संबंधित व्यक्तियों पर विभागीय जांच और दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. एसडीएम ने अपने पत्र में कहा है कि जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी, छल, बेईमानी और कूटरचना कर सरकारी राजस्व अभिलेखों में बदलाव किया गया. इस गंभीर अनियमितता को आपराधिक कृत्य मानते हुए विधि अनुसार केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया.

> बता दे कि जिन सात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है उनमें रवीन्द्र पिता स्वामीशरण, निवासी पैतिहा जिला प्रयागराज (उ.प्र.), भगोले पिता रामदास नाई, निवासी कोलहा, हनुमना, गल्होरे पिता भगोले नाई, निवासी कोलहा, लछिमन पिता भगोले, निवासी कोलहा, मिथिला प्रसाद पिता सुमंतराम, पूर्व पेशकार, तहसील हनुमना, यशोदानंदन दीपांकर, तत्कालीन पटवारी, हर्दिहाई, चन्द्रसेन पटेल कंप्यूटर ऑपरेटर, तहसील हनुमना शामिल हैं. पुलिस को आदेशित किया है कि दर्ज प्रकरण की विधिसंगत जांच कर कार्रवाई की जानकारी अविलंब उपलब्ध कराई जाए. साथ ही पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी मऊगंज को भी भेजी गई है.

कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया

पेड़ों की कटाई का विरोध करने जा रहे थे कांग्रेसी

सिंगरौली 22 नवम्बर. लंघाडोल थाना क्षेत्र के वासी बेरदहा में एक वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई कराए जाने को लेकर कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं.

डेढ़ दर्जन कांग्रेसी जंगल का हालात जानने एवं ग्रामीणों से मिलने जा रहे थे कि फाटपानी गांव में पुलिस ने कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया है. गौरतलब है कि वासी बेरदह में एक निजी कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है. जहां सरकार से अनुमति लेकर जंगलों की कटाई की जा रही है. वहीं ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं. इसी वस्तुस्थिति का जायजा लेने तथा ग्रामीणों से मुलाकात करने आज जिला कांग्रेस कमेटी की टीम स्थल पर जा रहें थे. जहां कांग्रेसियों ने दो बैरिकेट को जबरन पार कर तीसरे पर पहुंचने वाले थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उक्त कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की अध्यक्ष सरस्वती सिंह कर रही थी. इस दौरान डेढ़ दर्जन कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुये बस से पचौर पुलिस लाइन लाई है. पुलिस ने बैरिकेट फाटपानी गांव में लगाई थी. इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार एवं पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे.

कूनो के चीते ने किया कई पशुओं का शिकार

मुरैना, 22 नवंबर. मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में कुनो नेशनल पार्क से निकले एक चीते ने पशुपालक की खिरकाई पर धावा बोलकर सोलह भेड़ बकरियों का शिकार कर डाला. पशु पालक ने थाने पहुंचकर अपनी शिकार हुई भेड़ बकरियों के मुआवजे की मांग की है.

वन विभाग सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जसलावानी निवासी महीपत बघेल ओर नंदपुरा का भगीरथ बघेल जुगती पूरा खिरकाई पर अपनी भेड़ बकरियां रखते थे। कल जब भगीरथ का भाई वासुदेव बघेल खिरकाई में उन्हें देखने गया तो एक चीता उनकी बकरियों का शिकार कर रहा था.

हाईकोर्ट ने वादी का स्टे रोक पूरी तरह निरस्त कर दिया

- अपील खारिज, मंदिर का कब्जा वैध माना गया
- भूतेश्वर महादेव मंदिर भूमि का विवाद

शाजापुर, 22 नवंबर. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने शाजापुर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर से जुड़े भूमि विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा मांगी गई.

अस्थायी निषेधाज्ञा स्ट को निरस्त कर दिया है. न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि वादी अपना कब्जा साबित नहीं कर पाए और रिकॉर्ड के अनुसार जमीन पर मंदिर का लंबे समय से सतत कब्जा दर्ज है.न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने दिनांक 21 नवंबर 2025 को पारित आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार करने का निर्णय पूर्णत: उचित है और उसमें हस्तक्षेप का कारण नहीं बनता. हाई कोर्ट ने कहा कि मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक रिकॉर्ड मजबूत हैं. वर्ष 1919-20 से 1967-68 तक राजस्व अभिलेखों में भूमि पर भूतेश्वर महादेव मंदिर का ही नाम दर्ज है, 1985 और 2008 में नप द्वारा मंदिर के पुनर्निर्माण, नवीनी करण की अनुमति प्रदान की थी.

> अपीलकर्ताओं अक्षय कुमार जैन, अर्चना जैन, अर्पिता जैन द्वारा स्वयं पेश 1978 की नजूल एनओसी में पूर्व दिशा पर कुआँ व शंकर जी का चबूतरा का स्पष्ट उल्लेख है. 1990 में सिविल कोर्ट द्वारा भी मंदिर के कब्जे की पुष्टि की गई थी. न्यायालय ने कहा कि ये सभी रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भूमि पर मंदिर का कब्जा दीर्घकालिक व सतत रहा है. यह उल्लेख किया कि वादी अक्षय जैन आदि ने अपने शपथपत्र में स्वयं स्वीकार किया उन्हें 1957 का कथित विक्रय विलेख 11 अगस्त 2023 को पहली बार मिला.

प्रहलाद पटेल पहुंचे मां बगलामुखी मंदिर, मां का लिया आशीर्वाद

नलखेड़ा, 22 नवंबर. मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने शनिवार प्रात: गर्भ ग्रह में बैठकर मां बगलामुखी का स्वर्ण श्रृंगार दर्शन कर विधि विधान से मंत्रो उच्चारण के साथ पूजन अर्चन किया .

चित्रकूट में 2800 करोड़ से हो रहे कार्य

कलेक्टर एवं अध्यक्ष चित्रकूट विकास प्राधिकरण ने ली बैठक

सतना, 22 नवंबर. जिले के चित्रकूट का समग्र विकास राज्य शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता का विषय है.

चित्रकूट के समग्र विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा, पर्यटन के आकर्षण, प्राकृतिक सौन्दर्य को कायम रखते हुए धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए केन्द्र और राज्य शासन द्वारा स्वीकृत लगभग 2800 करोड रूपये लागत के विकास परियोजनाओं के कार्य चल रहे हैं. कलेक्टर सतना एवं अध्यक्ष चित्रकूट विकास प्राधिकरण डॉ. सतीश कुमार एस ने शुक्रवार को चित्रकूट नगर पंचायत के सभाकक्ष में संबंधित विभागों एवं कार्यकारी एजेंसी की बैठक लेकर चित्रकूट विकास के कार्यो की समीक्षा की. इस अवसर पर एसडीएम मझगवां महिपाल सिंह गुर्जर, सहायक कलेक्टर एवं सीएमओ नगर परिषद अनिकेत शांडिल्य, तहसीलदार कमलेश सिंह भदौरिया, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण बीआर सिंह, तकनीकी अधिकारी स्मार्ट सिटी दीपेन्द्र सिंह, अंशुमान सिंह, एमपीटीसी के अमित तिवारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे. चित्रकूट के विकास कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि मोहकमगढ तिराहे से पीली कोठी तक का मुख्य मार्ग 44 करोड 62 लाख रुपए लागत से बनाया जा रहा है.

> 30 मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है. इसी प्रकार 11 करोड 13 लाख रूपये की लागत से विभिन्न स्थानों पर भूमिगत विद्युतीकरण, 7 करोड 49 लाख रूपये की लागत से अमृत योजना में चित्रकूट के विभिन्न वार्डो में 60 किमी पाइपलाइन बिछाने, मंदाकिनी पैसुनी नदी के पुर्नजीवन के लिए 1.83 करोड लागत से झूरी नाला माइक्रोवाटर शेड के कार्य किये जा रहे हैं. इन सभी कार्यो को मार्च 2026 में पूरे करने का प्रयास किया जा रहा है. एम पी टीसी द्वारा 38 करोड 84 लाख रूपये लागत से कामदगिरी परिक्रमा पथ का पुर्निर्माण किया जा रहा है.

एक नजर में

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने पत्रक जमा किया

मंदसौर, 22 नवंबर. विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज उप मुख्यमंत्री एवं मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा ने स्वयं आगे बढ़कर अपना गणना पत्रक फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को जमा किया. उन्होंने मतदाता सूची में सुधार और अद्यतन प्रक्रिया को मजबूत बनाने हेतु यह महत्वपूर्ण कार्य किया. फॉर्म जमा करने के बाद श्री देवड़ा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरे जिले सहित पूरे प्रदेश में चल रहा है. यह लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. सभी पात्र मतदाता जिन्होंने अब तक अपना गणना पत्रक जमा नहीं किया है, वे शीघ्रता से अपना फॉर्म भरकर पूरी जानकारी के साथ बीएलओ को अवश्य जमा करवाएं, ताकि कार्य समय सीमा के भीतर पूर्ण हो सके. उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी मतदाता को फॉर्म भरने में कोई कठिनाई हो, तो वे तुरंत अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क करें. बीएलओ द्वारा सभी आवश्यक जानकारी एवं सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है. उप मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं गणना पत्रक जमा करने से मतदाताओं को सक्रिय रूप से पुनरीक्षण में भाग लेने का संदेश मिलता है तथा मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने में यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. जिला प्रशासन ने भी नागरिकों से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग दें और समय पर अपना गणना पत्रक भरकर जमा करें.

कांग्रेस की लड़ाई की बड़ी जीत हुई : भूरिया

झाबुआ,22 नवम्बर. मप्र हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती 2022 में एससी-एसटी अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय पर सख्त रुख अपनाते हुए नई संशोधित मेरिट सूची तैयार करने का बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 191 पदों में से 121 एसटी-एससी पद खाली रह जाना अत्यंत गंभीर' मामला है और चयन प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी को दर्शाता है. इस मामले में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने इस फैसले को आदिवासी समाज और कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत बताया है. डॉ. भूरिया ने बताया कि 121 सीटों में से आदिवासी समाज के अभ्यर्थियों के 0 चयन के न्याय को कांग्रेस पार्टी द्वारा आदिवासी समाज के साथ मिलकर लगातार पूरी बुलंदी से उठाया गया. डॉ. विक्रांत भूरिया ने इस मामले को भोपाल एवं दिल्ली स्तर तक भी पूरी बुलंदी से उठाया. जिसके परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय ने भी इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होने की बात कहते हुए नई संशोधित मेरिट सूची तैयार करने हेतु निर्देशित किया है.

कांग्रेस नेता पर हमला करने वाले पांच गिरफ्तार

ग्वालियर 22 नवंबर. कांग्रेस नेता को बेरहमी से पीट-पीटकर अधमरा करने वाले पांचों आरोपियों को थाटीपुर पुलिस ने पकड़ लिया है. पकड़े गए आरोपियों ने थाटीपुर थाना क्षेत्र के मेला ग्राउंड स्थित विवेक नगर में रात करीब दो बजे वारदात को अंजाम दिया था. वारदात कैमरे में कैद हुई थी. पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है. थाना प्रभारी विपेन्द्र चौहान ने बताया कि थाटीपुर स्थित मेला ग्राउंड के पीछे न्यू विवेक नगर निवासी सतेन्द्र सिंह कुशवाह भिंड के रहने वाले है और कांग्रेस नेता है. अभी वह सेवड़ा विधानसभा प्रभारी हैं. इसके साथ ही वह प्रॉपर्टी का कारोबार करते है. रात करीब 2 बजे वह एक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस आ रहे थे. अभी वह घर के दरवाजे पर पहुंचे और कार का गेट खोल रहे थे कि तभी आधा दर्जन बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया. वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही बदमाशों ने उन्हें जमीन पर पटका और मारपीट करना शुरू कर दिया. एक बदमाश ने उन्हें राइफल के बटों से पीटा. बदमाशों ने उनकी तब तक पिटाई की जब तक वह अधमरे ना हो गए. इसके बाद बदमाश वहां से भाग निकले. मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने जब कैमरे खंगाले तो एक बदमाश की पहचान शैलू कुशवाह के रूप में हुई. इसका पता चलते ही पुलिस ने उसकी तलाश की और थाटीपुर चौराहे से शुक्रवार रात दबोच लिया. उससे पूछताछ में पता चला कि उसके साथ वारदात में भरत सोलंकी, कुलदीप परिहार, बाल सिंह भदौरिया और रामस्वरूप गुर्जर शामिल थे. इसका पता चलते ही पुलिस ने उनकी तलाश की और उन्हें दबोच लिया है.

दामाद ने बेच दिया ससुर का ट्रैक्टर, पुलिस ने यूपी से बरामद किया

शिवपुरी. जिले के करैरा थाना सीमा ने आने वाले ग्राम लैंदा निवासी मलखान सिंह रावत ने अपने दामाद पर ट्रैक्टर हड़पने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है. फरियादी के अनुसार उन्होंने किस्तों पर लिया अपना स्वराज ट्रैक्टर 15 जनवरी 2024 को अपने रिश्तेदार व दामाद, ग्राम कल्याणपुर निवासी शिवराज सिंह रावत को एक महीने के लिए गन्ना मील पर ले जाने के बहाने दे दिया था. तय समय बीत जाने के बाद भी ट्रैक्टर वापस नहीं मिला.शक होने पर मलखान सिंह ने करैरा थाने में शिकायत की. पुलिस जांच में पता चला कि शिवराज ने ट्रैक्टर को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में व्यक्ति को 3.60 लाख में बेच दिया.

न्यू तैयबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सचिव पर एफआईआर

नवभारत न्यूज

रतलाम। फर्जी मान्यता प्रमाण पत्र और आयुक्त पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग के हस्ताक्षर की फोर्ज करने पर सचिव, न्यू तैयबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विरुद्ध डीपीसी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई।

स्कूल द्वारा फर्जी मान्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्रवाई

विभाग के अनुसार विद्यालय के पात्र छात्रों को आरटीई अधिनियम 2009 अन्तर्गत एडमिशन नहीं देने पर स्कूल की जांच करई। जांच में स्कूल के विरुद्ध 18 अगस्त को नोटिस जारी किया। नोटिस के उत्तर में स्कूल के लेटर हेड पर सचिव के हस्ताक्षर से जवाब प्रस्तुत कर आयुक्त पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग का भी मान्यता पत्र प्रस्तुत कर आरटीई अधिनियम 2009 से बाहर होने का उत्तर प्रस्तुत किया। जब उक्त पत्र पर आयुक्त के हस्ताक्षर संदिग्ध होने से पत्र की जांच की और आयुक्त कार्यालय से मार्गदर्शन लिया। कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पत्र जारी नहीं किए जाने की जानकारी दी और वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

> **जांच में पत्र निकला फर्जी**
>
> समिति द्वारा प्रस्तुत पत्र पर आयुक्त के हस्ताक्षर संदिग्ध होने से पत्र की जांच की। आयुक्त कार्यालय से मार्गदर्शन लिया। कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से ऐसे किसी पत्र जारी नहीं किए जाने की जानकारी दी गई और वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

हत्या के मामले में 13 को उम्रकैद

शिवपुरी, 22 नवंबर . मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल ने हत्या के एक मामले में 13 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है. न्यायालय द्वारा कल दोपहर इस मामले में यह फैसला सुनाया गया. अभियोजन के अनुसार पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम कछुउऔ में एक अक्टूबर 2022 को जमीन संबंधी विवाद के चलते अच्छे लाल रजक की गोली मारकर तथा धारदार हथियार से हमला करके उस समय हत्या कर दी गई थी, तब वह रामलीला देखने गया था। आरोपियों ने उस के शव को गांव के बाहर सड़क पर डाल दिया था. पता चला कि मृतक तत्कालीन सरपंच का समर्थक था.

फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र मामले में शिवपुरी कोतवाली में एफआईआर

- नीट यूजी मॉपअप काउंसलिंग में अभ्यर्थी पर किया केस

शिवपुरी, 22 नवंबर. यहां के मेडिकल कॉलेज में नीट यूजी 2025-26 की मॉप-अप काउंसलिंग के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. दिव्यांग कोटे से प्रवेश लेने आई एक अभ्यर्थी का दिव्यांगता प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया, कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट लाइब्रेरियन सत्येंद्र सिंह यादव ने कोतवाली में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि 8 नवंबर 2025 को अभ्यर्थी कु. श्वेता सिंह काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुई थीं. दस्तावेज सत्यापन के दौरान उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एस.एस. हॉस्पिटल द्वारा जारी एक दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया. कॉलेज प्रशासन ने जब इस प्रमाणपत्र को बीएचयू से सत्यापित कराया, तो यह पूरी तरह फर्जी पाया गया.

कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को अभ्यर्थी के नीट रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस स्लिप, प्रस्तुत किए गए फर्जी प्रमाणपत्र और बीएचयू द्वारा जारी फर्जी प्रमाणपत्र की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों की प्रतियां सौंपी हैं. कॉलेज ने अपने पत्र में ऐसे विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

एसआईआर को लेकर शासन सत्ता-विपक्ष सभी हैं मुस्तैद

सीधी 22 नवम्बर. एसआईआर को लेकर शासन-प्रशासन, सत्ता-विपक्ष सभी मुस्तैद हैं. एसआईआर के प्रगति को लेकर जहां प्रशासन से शासन अपडेट ले रहा, वहीं सत्ता और विपक्ष प्रशिक्षण देने में जुटा है.

जिले में चल रहे निर्वाचन नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 (एसआईआर) का कार्य काफी तेजी के साथ चल रहा है. प्रशासनिक स्तर से जहां बीएलओ मतदाताओं को गणन पत्र वितरित करके उनको जमा कराने के पश्चात डिजिटाइजेशन कार्य कर रहे हैं वहीं सत्ता-विपक्ष भी एसआईआर को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हैं. सत्ता और विपक्ष दोनो की ओर से अपनी सक्रियता प्रदर्शित करते हुये सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने में जुटे हुये हैं. बीएलओ से मिले गणना पत्र सही तरीके से भरकर जमा हो सकें इसके लिये भी अभियान चलाकर सहयोग किया जा रहा है. एसआईआर के प्रगति की प्रतिदिन की जानकारी शासन जिला प्रशासन से ले रहा है. एसआईआर की प्रगति जिन क्षेत्रों में न्यून मिल रही है वहां बीएलओ के विरूद्ध कार्यवाही भी हो रही है. 4 दिसम्बर तक किया जा रहा है. प्रथम चरण में वर्ष 2003 एवं वर्ष 2025 में शामिल मतदाताओं के नाम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गणना पत्र को भराने एवं जमा कराने का काम किया जा रहा है.

आयोजन उप मुख्यमंत्री ने किया रैबीज ट्रैक पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ

अस्पतालों को सेंटर ऑफ आर्ट के रूप में करेंगे विकसित

ग्वालियर, 22 नवंबर. गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यह संस्थान न्यूरोसर्जरी जैसे क्षेत्रों में वह कार्य 65 वर्ष पहले कर चुका है, जो कई स्थानों में अब शुरू हो रहे हैं.

इसी उत्कृष्ट परंपरा के कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं इससे जुड़े अस्पतालों को सेंटर ऑफ आर्ट की तरह विकसित किया जाएगा, जिससे मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा यहीं उपलब्ध हो सके और रेफर करने की आवश्यकता न पड़े. डिप्टी सीएम शुक्ला ने यह बात रैबी ट्रैक पोर्टल के वर्चुअल शुभारंभ के अवसर पर जीआरएमसी के बोर्ड रूम में उपस्थित चिकित्सा शिक्षकों व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने इस नवाचार को भारत सरकार के संकल्प रेबीज मुक्त भारत की दिशा में अत्यंत आवश्यक कदम बताया. डिप्टी सीएम शुक्ला ने बताया कि ग्वालियर में प्रतिवर्ष 7 से 8 हजार रेबीज मरीज अस्पताल पहुंचते हैं. कई मरीज जागरूकता के अभाव में समय पर वैक्सीनेशन नहीं लेते, जिससे उनकी जान तक जोखिम में पड़ जाती है. उन्होंने कहा कि रैबी ट्रैक पोर्टल मरीजों के मोबाइल पर समय-समय पर वैक्सीन की डोज की तिथि का संदेश भेजेगा, जिससे वे समय पर उपचार ले सकेंगे. उन्होंने आगे कहा कि मेडिकल कॉलेजों का दायित्व है कि वे नवाचार करते रहें, क्योंकि भारत सरकार टीबी मुक्त भारत अभियान और रेबीज मुक्त भारत जैसे कई महत्वपूर्ण मिशन चला रही है.

> उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आयुष्मान योजना में 60 करोड़ से अधिक नागरिक कवर हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हुआ है. उन्होंने जीआरएमसी प्रबंधन व कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग को इस नवाचारी प्रयास के लिए शुभकामनाएं दीं. इस दौरान महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ. आरकेएस धाकड़ ने बताया कि यह ऑनलाइन पोर्टल कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा विकसित किया है .